(iv) Need for more financial assistance to Orissa for boosting tourism.

SHRI NITYANANDA MISRA (Bolangir): Orissa is described as a State of immense tourist attractions. Numerous old places and buildings ancient caves and temples with their unique architecture and fine sculpture, picturesque sea beach and fascinating lakes, famous cultural and religious events and festivals, are Orissa's tourist assets. Though Konark, temple of Lord Jagannath and atha Jatra of Puri have abiding interest, Harishankar and Ranipur Jhariel of Bolangir District which have great potential as places of tourist attraction have not yet received the attention they richly deserve, Ranipur Jhariel with the beautiful sculpture of the statutes of the ancient temple and the new excavations and findings about Jogini's which have great historical and archeological importance is a rare ancient monument which deserves to be projected to limelight. Harishankar temple situated at the fact of the majestic Gandamarda mountains by the side of a waterfall whose water is considered hold by thousands of pilgrims who rush to have a darshan of Lord Harihara after a holy bath in the waterfall is a place of pilgrimage. The captivating scenic beauty of these two places coupled with historical and archeological significance can develop into tourist centres of great importance. The promotion of tourism can substantially contribute to the economic prosperity of the State. There is vast scope and potential for rapid expansion of tourism in Orissa and Centre should provide more funds to the State Government for opening recreation centres and tourist facilities.

(v) Demand for making 'Bhabhad' grass available at reasonable rate to 'Bann' labourers in Dhar areas of U.P.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उत्तरप्रदेश के जिला सहारनपुर का उत्तरी भाग शिवालिक पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। करीब 45 किलोमीटर लम्बा और 8 किलोमीटर चौड़ा रेतीला, पथरीला व असिंचित यह क्षेत्र घाड़ के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों में लकड़ी काटना, भाभड़ काटना, पत्थर ढोना व कभीकभी खेतिहर मजदूरी को छोड़कर यहां के निवासियों की मुख्य जीविका भाभड़ नाम की घास से बान बनाकर चलती है। एक मुद्दत से 40 हजार लोगों की जीविका इसी धंधे पर टिकी हुई है। इस वर्ष से पहले तक वन विभाग भाभड़ ठेकेदारों को नीलाम करता और ये ठेकेदार प्रत्येक गांव के व्यापारियों को थोक में भाभड़ बेचते और तब साधनहीन और आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा हुआ बान मजदूर इन व्यापारियों से उधार भाभड़ लेकर 100 से 125 रुपए माहवार पर अर्द्ध जीवित हालत में अपना व अपने परिवार का गुजर-बसर करता चला आ रहा है। यही इन मजदूरों की पारिवारिक मजदूरी थी।

इस वर्ष वन संपत्ति में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने एक उत्तरप्रदेश वन निगम की स्थापना की है, जिस का कार्य वन संपत्ति का अपने हाथों से फुटकर क्रेता को बेचना है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत वन निगम खुद भाभड़ घास को भी नीलामी तौर पर बेच रहा है। किंतु अफसोस की बात है कि जनता का आशा के विपरीत वन निगम भाभड़ को पहले से डेढ़ गुना और इससे अधिक भाव पर बेच रहा है, जिससे बान मजदूर परिवार की तुच्छ मजदूरी 100-125 रुपए भी एकदम समाप्त हो गई है। वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। यदि भविष्य में भी यही स्थिति बनी रही तो इसमें जरा भी संदेह नहीं कि क्षेत्र के 40 हजार लोग बिलकुल तबाह हो जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस भयंकर समस्या को गौर करके अविलंब बान मजदूरों को उचित दर पर भाभड़ मुहैया कराने की व्यवस्था करें।